भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2282
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

राजस्थान में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति

2282. **श्री भजन लाल जाटवः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में, विशेषकर करौली तथा धौलपुर जिले में, आंगनवाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.) भवनों की कुल संख्या कितनी है और जीर्ण-शीर्ण, क्षतिग्रस्त, किराए के या भवन-हीन परिसरों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या उक्त भवनों के पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत के लिए कोई विशेष केंद्रीय सहायता अथवा विशेष परियोजना प्रस्तावित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और
(ग) जर्जर भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं अथवा बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ किसी दुर्घटना अथवा चोट लगने की स्थिति में जवाबदेही किस स्तर पर निर्धारित की जाएगी तथा ऐसे असुरक्षित भवनों को तत्काल सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) राजस्थान राज्य सहित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों की जिलावार संख्या पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड के लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ समन्वय के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण का प्रावधान है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम इत्यादि से आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए निधि प्राप्त करना जारी रखने की सलाह भी दी गई है।

पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत, पीवीटीजी (विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों) वाले क्षेत्रों में निर्माण के लिए कुल 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 51 आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान राज्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय बहुल गांवों में तालमेल, आउटरीच और संतृप्ति (saturation) पर ध्यान केंद्रित करता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, निर्माण के लिए 875 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 135 आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान राज्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं ,जिसमें करौली जिले के लिए 9 आंगनवाड़ी केंद्र और धौलपुर जिले के लिए 1 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ स्थान उपलब्ध है, सह-स्थित (co-locate) किया जाए। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों को सह-स्थित करने के दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं।

साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवसंरचना की सुविधाओं में सुधार के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹17,000/- प्रति केंद्र और शौचालयों के निर्माण के लिए ₹36,000/- प्रति केंद्र की दर से निधि प्रदान की जाती है। देश भर में राजस्थान के 11,665 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल 1,58,966 आंगनवाड़ी केंद्रों और शौचालयों के निर्माण के लिए कुल 1,42,522 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के दायरे में आता है। लाभार्थियों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से उनके साथ निरंतर बातचीत और वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की जाती है।

******